

(ग) क्या उक्त परियोजना को उनकी अपनी-अपनी नदियों से पानी मिलेगा जिनके सम्बन्ध में अन्तर्राजीय भागीदारी की गई है और जहां तक लागत और लाभ के पहलुओं का सम्बन्ध है, भागीदार राज्य अपने अंश की मांग कर रहे हैं;

(घ) क्या पह भी सच है कि पंजाब उपरोक्त परियोजनाओं में अन्य राज्यों को अंश देने के लिए तैयार नहीं हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो किन आधारों पर तथा केन्द्रीय सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख). आनन्दपुर साहिव तथा मुकेशियां जल विद्युत परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है। अपर बारी दो आव नहर चरण-II थोन बांध परियोजना का एक भाग है, इसे भी पंजाब सरकार द्वारा हाथ में लिया गया है। आनन्दपुर साहिव और मुकेशियां के संबंध में इन परियोजनाओं से होने वाले लाभों में अपने हिस्से के लिए राजस्थान और हरियाणा ने दावे किए हैं। प्रस्ताव यह था कि इन दावों को एक मध्यस्थ को सौंप दिया जाए, वश्ते कि ये राज्य इस बात पर सहमत हो जायें कि उसका निष्कर्ष सभी संबंधितों के लिए आवद्धकर होगा। ऐसी कोई सहमति प्राप्त नहीं हो पाई है। अतः इस दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

(ग) और (घ). इन तथा ऐसी ही परियोजनाओं के मामले में लाभों में हिस्से के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा किसी न किसी आधार पर परस्पर-विरोधी दावे किए गए हैं। इन मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्यों के साथ विचार-विश्वार्थ आरम्भ किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने यह प्रस्ताव भी किया है कि विभिन्न परस्पर विरोधी दावों का समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक ऐसी परियोजनाओं की केन्द्रीय सेक्टर में यह केन्द्रीय सहयोग से हाथ में

लिया जा सकता है और दावों को परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान निपटाया जा सकता है।

Setting up of polyester units in backward areas

5700. SHRI KAMAL NATH : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether there are proposals to set up five new polyester units in backward areas in various States;

(b) if so, the areas selected in Madhya Pradesh for the purpose; and

(c) whether any progress has been made in this direction so far ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P.C. SETHI) : (a) to (c). A number of applications for setting up new polyester staple fibre units in various states have been under consideration of Government. A final decision on the applications including that of the Madhya Pradesh State Industries Corporation Limited is yet to be taken.

प्लास्टिक उद्योग

5701. श्री मूस चन्द डागा : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृता करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि के कारण प्लास्टिक उद्योग की हालत बहुत गम्भीर हो गई है और इसके परिणामस्वरूप बहुत से एककों के बन्द होने की सम्भावना है और यदि हाँ, तो कितने एकक पहले ही बन्द हो चुके हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि देश में 6000 प्लास्टिक प्रोसेसिंग एकक हैं और यदि हाँ, तो उनमें 1979-80 और 1980-81 में कितना उत्पादन हुआ और उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं?